ٹھیک ہے - کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی اور ان دو فرموں نے کروڑ سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا - میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں کوئی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی اور اگر ہوئی تو کیا ایکشن لیا گیا ان دونوں فرموں اور افسروں کے خلاف -]

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक उनके सवाल का ताल्लुक है यह मामला एस्टीमेट्स कमेटी के पास है और मेरे लिये यह मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस पर कोई तबसरा करूं क्योंकि यूल की जो एक्सपोर्ट पोलिसी थी उसी के तहत जो एक्स्पोर्टर्ज हैं उनको हक दिया गया था कि कुछ नायलोन भी मंगाये। यह सारा मामला जो है यह एस्टीमेट्स कमेटी के सुपुर्द किया गया है इसलिये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नायलोन के धागे की देश में काफी मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि देश में यह कितना पैदा होता है और विदेशों से आप कितना मंगाते हैं और कुल कितनी हमारी आवश्यकता है? क्या यह भी सच है कि इस की वजह से जो सूती धागा है उसकी मांग कम हुई है और इस कारण से कुछ मिलें बन्द होने जा रही हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक नायलोन के धागे का ताल्लुक है यह धागा सूती धागे से बिल्कुल अलग है। सूती धागा कपास से बनता है और यह कैमिकल प्रोसेस से बनता है। चूंकि इसकी कमी है इस वास्ते इस को बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर हमारे यहां इसकी पैदावार काफी मिकदार में हो तो बाहर से मंगाने की जरूरत ही न पड़े और इसका सवाल ही न उठे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कितना यहां पैदा होता है और कितना विदेशों से मंगाते हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस वक्त तकरीबन नौ करोड़ रुपये के माल के एस टी सी ने आर्डर दिये हैं। इस में से तकरीबन छः करोड़ रुपये का माल इस वक्त तक पहुंच चुका है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम बनाते कितना हैं और मांग कितनी है, क्या इसके आंकड़े आप नहीं दे सकते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सही फिगर्ज नहीं दे सकता हूं। जहां तक मेरा ख्याल है हमारी जरूरियात दस टन के करीब की हैं और पैदावार मेरे ख्याल में चार पांच टन के करीब है।

दक्षिण में सूती मिलों का बन्द होना

992. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में सूत कातने तथा कपड़े की मिलों के के बंद हो जाने की आशंका है;

(ख) क्या मिल मालिकों का विचार अपने श्रमिकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में कटौती करने का है; और

(ग) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगी?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) There is no apprehension of large-scale closure of cotton spinning mills in South India.

(b) and (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अब इस का क्या मतलब हुआ ? 21 दिन पहले हम ने नोटिस दिया । दस दिन के बजाय 21 दिन की नोटिस मिले और फिर यह कह रहे हैं कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तो यह क्या मजाक बना रहे हैं ? हाउस आफ कामन्स में दो दो तीन दिन की नोटिस पर सवाल पूछे जाते हैं और आप को हम 21 दिन की नोटिस देते हैं तब भी जवाब नहीं मिलता है ।

क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि बहुत सारे मिलों के मालिक, जो अच्छी मिलें हैं उन की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं । वित्तीय और मालो घोटाल करते हैं, मिलों का दिवाला निकालने हैं, छंटनी होती है और मिलें बन्द हो जाती हैं, और फिर मजदूर के ऊपर दबाव डाला जाता है कि अगर बेरोजगारी से बचना है तो महंगाई भत्ते में और वेतन में कटौती स्वीकारो, तब जा कर हम मिल खोलेंगे तो, मैं जानना चाहता हूं कि कम वेतन पर और कम महंगाई भत्ते पर कितनी मिलें हमारे देश में चल रही हैं और क्या फिलहाल दक्षिण की 16 सूती मिलें बन्द होने की खबर उन के पास पहुंची है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जहां तक जनूबी हिन्द का ताल्लुक है इस वक्त तक 6 मिलों ने वहां पर नोटिस दिया है कि वह अपने कारखाने बन्द करेंगी । उस में चार मिलों को गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मिलों में जो स्टाक जमा हुआ है उस की तादाद इतनी नहीं कि कोई एलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई हो, एक तरफ से तो मिलें कहती हैं कि हमारा कपड़ा नहीं बिक रहा है और दूसरी तरफ मांग की जा रही है कि कन्ट्रोल वैराइटी के कपड़े की कीमत बढ़ाई जाय और फिर दूसरी चीज यह है कि काटन की जो पैदावार हो रही है उस पर ग्रोअर को उस की असली कीमत मिले तो इस में ग्रोअर का इन्टरेस्ट, ट्रेडर का इन्टरेस्ट और अल्टीमेट कन्ज्यूमर का इंटरेस्ट सभी कुछ हम मद्देनजर रख रहे हैं । यह तमाम बातें जेरे गौर हैं और मैं समझता हूं कि हमारे मिनिस्टर आज इस के मुताल्लिक कोई बयान भी दे रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का और उत्तर का कोई ताल्लुक है ? कोई रिश्ता है । मैंने क्या सवाल पूछा था ? मैंने आप से यह जानकारी चाही थी कि इस समय जो बन्द मिलों को आप ने चालू किया मदद दे कर उन में कितनी मिलों में कम वेतन पर मजदूरों को काम करना पड़ता है क्योंकि मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता था कि मजदूरों का वेतन घटाने के लिये यह साजिश की जा रही है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जहां तक हमारी इत्तिला है गवर्नमेंट ने जो वहां मदद दी है वह इसी गरज से दी है कि उन की मजदूरी में किसी किस्म की कमी न हो और वह कारखाने चालू रहें ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं कई दफा आप को कह चुका हूं कि जैसे

जब्बे को जो तैयारी करके नहीं आते हैं, हमारे समय में कम से कम उन को बाहर खड़ा किया जाता था तो दिनेश सिंह साहब को दस मिनट के लिए बाहर खड़ा किया जाय जिस से कि अगले दौर वह तैयार हो कर आयें।

अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह भी सही है कि इस वक्त एक नया कारण यह भी हुआ है मिलों के बन्द होने का कि मिल वाले जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं उन को उचित दाम नहीं देना चाहते हैं ? दामों को गिराने के लिये क्या जानबूझ कर उन्होंने खरीद बन्द की है और मिलों को बन्द करने की धमकी दे रखी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जी हां, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बात कुछ सच मालूम होती है। लेकिन मैं यह जरूर अनुरोध करूंगा कि अगर उन को दस मिनट के लिए बाहर भेज दें तो सदन का काम ज्यादा अच्छा चलेगा।

श्री मधु लिमये : अरे, थोड़ा सा शर्म रखो।

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: Is the minister aware that this racket of closure of mills is a mechanism invented by private traders for the sole purose of funnelling out into private pockets what is public money and thereby floating the sinking mills at the cost of public money, thereby again opening out a few more channels of funnelling out public money by handing over the closed mills for management purposes to private parties?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The Government is aware of all that is happening in the textile industry and Government is taking the necessary steps. We are having a debate now.

SHRI S. KANDAPPAN: In the original reply, the minister stated that it is not very serious. But I am afraid it has not been properly appreciated by the ministry here because, ther are already cases where mills have been closed and they have been reopened after the guarantee of credit by the State Government. Even after that, they are not running properly and there is again a threat of closure. Our information is more than 15 mills are on the verge of closure. They say that the accumulated stock of yarn is of a higher count and so, the value of money that is involved in this is comparatively higher. They allege that the Government calculation is not correct. Then they say they are not in a position to modernise the mills. I would like to know whether the Central Government are in a position to help the industry to modernise the machinery and to clear the burden of accumulated stocks on them.

SHRI DINESH SINGH: My colleague had mentioned that the stocks are not alarming and I would only like to repeat that. About modernisation, the House is aware of the magnitude of the problem of the textile industry in this country and it will not be possible for Government to say that they can immediately set this right, because it is not wholly the responsibility of Government. It has been gradually allowed to get into this position. I have tried to explain on a number of occasions that there has not been enough ploughing back and enough modernisation effort by the industry. It is a tremendous problem and it is seriously engaging our attention. We shall do our best to help them to modernise them and work them efficiently.

SHRI S. KANDAPPAN: It is a very serious question. I have collected information from various sources and I have been told that the yarn which is accumulated there is of high count and the value is more. If you take that into account, really they are not in a position to meet the credit needs.

SHRI DINESH SINGH: The point is they have to sell them. What is the point in accumulating them? They have to sell either in the home market or the international market.

SHRI PILLO MODY: The Minister has said that they are aware of what is happening and that they are taking some action. They will not allow the punitive effect of a free market economy to take its own action on delinquent textile mills.

SHRI RANGA: Not delinquent.

SHRI PILLO MODY: There are many which are delinquent. At the same time, they will not categorically state as to what action they are taking to meet certain circumstances within the textile industry. They merely say "we are considering this, we are taking action, we know all about those things". Why don't they, at one time or the other, say "we intend to do this or that in such special circumstances"?

SHRI DINESH SINGH: I am sorry that the hon. Chairman of the Bhim Club had to get up to ask this question.

SHRI PILLOO MODY: I hope that this reply will be commensurate with my effort.

SHRI DINESH SINGH: I can only say that I shall be delighted to sit with him and try to find a solution to this problem, if he has any suggestions.

SHRI M. B. RANA: Are the government aware that the closure of mills and thereby creating unemployment is an indirect pressure on the Government so that they are able to buy cotton at a cheaper rate from the farmers?

MR. SPEAKER: That was asked earlier by Shri Madhu Limaye. Anyway it can be answered.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: Mr Speaker, Sir, the question has been asked but has not been categorically replied in the affirmative by the Government. Let them deny it or affirm it.

MR. SPEAKER: I think he has agreed. He said that to bring down the price this is being done.

SHRI S. K. TAPURIAH: Sir, you will kindly recall that it was about a month back that I expressed my fears in this House that if this Ministry does not act with urgency quite large number of mills will have to close down. It appears that it is idle to expect some work from this Ministry because I am told that between the Commerce Ministry and Industries Ministry there are 1,700 files lying pending because the Ministers do not have enough time to look into the jobs for which they are paid by the people of India. On this particular question the Minister and the Deputy Minister have tried to confound the House, confuse the House and mislead the House by two different statements. The Deputy Minister said that 6 mills were to close, closure in 4 mills has been averted because the State Government has given them some financial assistance. The Minister says that the question of giving more credit does not arise because the accumulation of stock does not help, the stocks have to be cleared, even by export if necessary. How do we reconcile these statements? Someone says that financial assistance is given and somebody else says the giving of financial assistance will not help because the stocks have to be cleared. May I ask whether as a constructive attempt to solve this problem he is prepared to give themselves for export of this yarn that has been accu-

mulated and rather than givig these incentives in terms of only cash they will permit the import of certain raw materials required by the textile industry and of which they are in short supply? For example, is he prepared to give incentive to mills for the import of nylon or polyster fibre which are in short supply, against the export of cotton yarn?

SHRI DINESH SINGH: I am not quite sure whether the hon. Member was making a speech on the Demands of the Ministry or asking a question. What he has asked is a basic policy question which, if I may say so with due respect to him, could have better been asked a few hours later when the Demands come up for discussion so that I may be able to give a more detailed reply.

SHRI S. K. TAPURIAH: How can we ask such questions during the Demands? Yesterday we raised the question of the import trade control policy. At the last moment he brought in the import trade policy and he asked us to discuss it in two minutes.

MR. SPEAKER: I am afraid he would not get a chance to speak on this even on the Demands.

SHRI S. K. TAPURIAH: Even my party cannot speak. Please give me one minute to explain the issue. The announcement about the import trade control policy was announced in the House a few minutes before the Demands of the Ministry were taken up. How do you expect members to speak and read at the same time and then offer comments? That is very unfair.

SHRI PILOO MDY: Unfortunately, the Minister thinks everybody studies in the same fashion as he does.

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है, इस लिये मैं कामर्स मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि जो लोग मिलें बन्द करने की धमकी दे रहे हैं या लेबरर्स को तंग करने के लिये मिलों को बन्द कर रहे हैं, क्या सरकार उन को नैशनलाइज कर के कोआपरेटिव बेसिज पर चलायेगी, जिससे कि कपड़े का संकट देश से दूर हो और गरीबों को कपड़ा मिल सके ?

श्री दिनेश सिंह : जो दवा माननीय सदस्य ने बताई है, वह दवा तो अच्छी है, लेकिन उसके बनाने में भी काफ़ी सिरदर्द है। हम ने जो विधेयक यहां पर रख था और जिसको इस सदन ने माना है, उस के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इन को रेग्यूलेट कर सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ मिलें इस लिये बन्द हो रही हैं या बन्द की जा रही हैं कि उन के मालिक, जिस जमीन पर मिलें खड़ी हैं, उस जमीन को बेच कर या उस पर मकान बनाकर उसके द्वारा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं। बम्बई की एडवर्ड मिल का मामला मंत्री महोदय के सामने आ चुका है। 7 जुलाई, 1967 से मिल बन्द है, एक प्रतिनिधि मण्डल भी मंत्री महोदय से इस सिलसिले में मिला था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस मिल को चालू करने के बारे में क्या किया जा रहा है ? क्या मिल मालिकों को छूट होगी कि मिल को बन्द कर के मकान बना कर मुनाफ़ा कमायें ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी छूट नहीं होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं ने कहा था कि एक प्रतिनिधि मण्डल उस मिल के बारे में मिला था। क्या उस मिल को चालू करने के बारे में सरकार कोई कदम उठा रही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : भूपाल का मामला भी उलझा पड़ा है ।

श्री तुलशी दास जाधव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार की मिलों को हाथ में लेने और उन को चालू करने के लिये एक बिल पास हुआ है । शोलापुर में दो-ढाई करोड़ रुपये की जायदाद धूल खाते में पड़ी हुई है, 6 हजार काम गार बेकार हो गये हैं, इस कानून के अनुसार या इस का डिपार्टमेंट इस मिल के बारे में क्या कर सकती है इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिये ?

श्री विनेश सिंह : इस कानून के मुताबिक सरकार क्या कर सकती है, यह तो कानून में लिखा है । जिस विशेष मिल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, वह चार साल से बन्द है । इस बिल के मुताबिक एक एक कारखाने को देखना पड़ेगा, कौन मिल चल सकती है, उस के लिये कितने खर्च की जरूरत होगी । ये सब बड़े पेचीदा सवाल हैं—इस लिये एक दम मेरे लिये कह देना कि उस को चलायेंगे या नहीं चलायेंगे यह कैसे सम्भव है ।

SHRI NATH PAI: May I know from the Minister whether the Government intends to follow its own policy, which was announced with so much fanfare, about the creation of the Textile Mills Corpoartion of India, or to rollow the advice, as it is customary with them, of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, which has asked for one abolition of the excise duty and also for removal of the control? In this context may I know why it took seven long months to help the workers of the Edward Mills, who have given to Government Rs. 45 lakhs of their precious savings in the form of provident fund, to run the mills? Why did it take such a long time when he had armoured himself with this power, by assuring the country and particularly Parliament that he will ensure that no single mill is forced to close down or a single employee is thrown out of employment? What prevented him from taking atcion? I want a reply, if possible, to both of my quetsions.

SHRI DINESH SINGH: The hon. Member knows very well that the function of the Textile Corporation is entirely different from the function of the Federation.

SHRI NATH PAI: Which of the two does he want to follow??

SHRI DINESH SINGH: We are going to follow the judgment which Government make of the situation. The Textile Corpoartion has certain functions. The Federation represents the industry. Both of them will be consulted as and when necessary. As regards the specific case of the Edward Mill that has been referred to by the hon. Member, he knows that it is a matter in which we have to act in consultation with the State Government. He is aware of the effort that we are making to start the mill. It is very diffcult for me to put down a dateline or to say that this will be done except to say that we are doing our best. It is a very difficult industry. Everybody has talked about the position it has gone into. All this trouble that has been created over nearly 50 years of this industry cannot be set right in 15 months.

SHRI NATH PAI: A more important question was: What is their reaction to the demand for abolition of controls; are they going to give in to this demand? It has happened in the past. The Fedeartion of Chambers of Commerce and Industry has

come out yesterday with a resolution demanding the abolition of controls. May we know what is the Government's thinking on this issue?

SHRI DINESH SINGH: Government's thinking on this issue is that we should retain control over a section of production of cloth which in our judgment would be essential for mass consumption so that we are able to maintain a reasonable price and the price does not jump up.

SHRI P. G. SEN: Has the Government looked into the question of diversion of capital by one mill to another and as a result the closure?

SHRI DINESH SINGH: I cannot say offhand.

SHRI ANBAZHAGAN: In the present crisis of the textile mills in order to avert the impending closure of sick mills in Tamil Nad the Madras Government has come forward to take over such mills and run them on behalf of the Government but in such cases the Government has to spend a lot of money in order to revive such mills and put them in a working condition. Will the Central Government come forward with any financial assistance to such a proposal of the Madras Government?

SHRI DINESH SINGH: Subject to the limitation of finances of the Central Government we shall certainly assist the Madras Government.

SHRI MANUBHAI PATEL: The hon. Minister has just now said that the Central Government has to take action in consultation with the State Governments. In certain cases where the State Governments have already recommended the taking over of certain mills, why is the Central Government hesitating to appoint authorised controllers over them?

SHRI DINESH SINGH: We can discuss the question mill by mill if you so desire but the point is that the Central Government have also to commit certain funds as their guarantee and they have also to satisfy themselves whether the guarantee that they are giving is economic or whether it will be returned or not. That is why each question has to be examined on merits.

SHRI RANGA: Some reference has already been made to one of the suggestions made by the Madras Government. Some time ago the Madras Government was approached by the millowners and they had some discussions. The Madras Government offered some support in some direction. May I know whether Government would be willing to get into a conference of not only the State Governments concerned in the South —in Madras more than one lakh workers are employed in these mills— but also with the State Bank of India and other banks and the Reserve Bank in order to facilitate the supply in adequate proportions of credit for different types of their stocks and their various productive activities so that they can all be helped to keep these people employed and at the same time can go on with their productive activities?

SHRI DINESH SINGH: I have on a number of occasions discussed this matter with the Chief Minister of Madras and we were able to give him certain assistance when he has asked for it. Of course, we had our difficulties and our limitations and obviously we could not fulfil the entire expectations that he had. As regards holding a larger meeting, certainly we shall at a suitable time call a larger meeting. It is our endeavour to get some kind of a working plan which we can then discuss with the State Governments, banks and others.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि अभी तक इस क्षेत्र में 16 मिलें बन्द हो चुकी हैं और करीब 35 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं, अब इसके क्या कारण हैं या क्या दिक्कतें हैं वह जो मिल मालिक हैं, कुछ और बताते हैं और सरकार का जजमेंट कुछ दूसरा है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो मिलें बन्द होती रहती हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने और रास्ता निकालने में देर होती रहती है इसलिए क्या कोई ऐसी मशीनरी या एथारिटी बनायेंगे जो कि, जब मिलें बन्द हों तब उसके कारण मालूम करके, अगर मिल-मालिक कुछ गलती करता है तो उसे मजबूर किया जाय उसे ठीक करने के लिए या अगर सरकार उसमें कुछ मदद देकर उसे ठीक कर सकती है तो यह सरकार करे ? क्या इस प्रकार की एक परमानेन्ट एथारिटी बनायेंगे जिससे कि मजदूरों को भी दिक्कत न हो और जो उपभोक्ता हैं उनको भी तकलीफ न हो ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह की मशीनरी अभी भी है जिसके हिसाब से इन्वेस्टीगेशन होता है और मिलें भी कुछ सरकार लेती ही है। हमने काफी मिलें ली हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी मिलें हैं जो कि बहुत पुरानी हो गई हैं या जिनमें इतनी गड़बड़ी हो गई है कि यदि सरकार उन को लें तो भी उनको एकदम से चलाया नहीं जा सकता है। तो यह सब कठिनाइयां हैं, यह बात नहीं है कि अगर कोई मिल बन्द हो जाती है तो सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। बहुत सी मिलें तो ऐसी हैं कि जिनको कोई भी सरकार नहीं चला सकती है।

इसके बाद जहां तक परमानेन्ट मशीनरी की बात है, हम टैक्सटाइल कारपोरेशन जो बना रहे हैं उसमें कुछ देर हुई क्योंकि रुपए का इन्तजाम करना पड़ा, कुछ और भी दिक्कतें थीं, अब उसकी इजाजत मिल गई है और जहां तक मेरा ख्याल है, मन्त्रालय से उसको रजिस्टर करने का भी इन्तजाम हो गया है। जैसे ही वह रजिस्टर हो जायगा, वह बन जायेगा तो उसके जरिये हम यह काम करने की कोशिश करेंगे।

SHRI AMRIT NAHATA: Besides mismanagement and unproductive wastefulness of textile mills the main reason why textile mills close down is that the entire textile industry in our country is absolutely wasteful. While Japan produces only 200 varieties of standardised cloth we in our country have 20,000 varieties. Would the Minister consider the imposition of minimum standards of cloth so that the entire textile industry is put on sound economic footing?

SHRI DINESH SINGH: I shall be very glad to consider it—in fact, I have been considering it and I have also been talking about it—but we have a variety in this country and people prefer different kinds of cloth. If it is the wish of the House that I do it, I shall be very glad to do it but then we shall have the problem of hon. Members saying that they cannot get the particular variety that they have been wearing.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा कि उस मिल की जमीन को बेच कर मकान बनाने की छूट मालिकों को नहीं दी जायेगी। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उस मिल के मजदूरों ने अपने प्राविडेन्ट फण्ड की रकम में से 45 लाख रुपया उस मिल को चलाने के रिये सूबे की सरकार को दिया लेकिन उसके बाद में आफिशल लिक्वीडेटर ने ऐसा हुक्म दे दिया कि वह मिल न चलाई जाए ?

दूसरी बात यह है कि इस मिल की मद्रास में जो पुरानी जमीन थी उस जमीन को एक साल पहले, जो उसका असली दाम था वह दाम न बता कर कुछ कम दाम में बेचने का काम मालिकों ने किया है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का कुछ हिस्सा माननीय सदस्य ने पिछली मर्तबा भी पूछा था और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जवाब भी दिया था । एक दम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या जवाब दिया था, मैं माननीय सदस्य को उसकी सूचना दे दूंगा ।

श्री ओ० प्र० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि मिल मालिकों के पास बहुत बड़ा कपड़े का स्टाक पड़ा हुआ है और वे उसको फिक्स्ड दाम से कम दाम पर भी बेचने के लिए तैयार हैं इसलिए क्या सरकार उन मिलों की सहायता के लिए इतना काम करने के लिए तैयार है। कुछ परसेन्ट, 40 परसेन्ट या 50 परसेन्ट कपड़ा डि-कंट्रोल कर दे ताकि वे अपनी इच्छानुसार कीमत पर कपड़ा बेच सकें ?

श्री दिनेश सिंह : बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा कहां पड़ा हुआ है, यह मुझे नहीं मालूम है । दूसरे यह कि अगर कम दाम पर कपड़ा बिक रहा है तो यह बड़ी खुशी की बात है । अब 40 परसेन्ट पर तो कुल कन्ट्रोल है, अगर उसको भी हटा दें तो कन्ट्रोल क्या रह जायेगा ।

श्री श्रीचन्द गोयल : पिछले वर्ष हमारा जी कपड़े का निर्यात है वह दो करोड़ 40 लाख मीटर कम हो गया है, क्या इसका कारण यह है कि मिल अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकीं या उसके दूसरे कोई कारण हैं जो इतनी भारी कमी हमारे कपड़े के निर्यात के अन्दर हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : इसके कई कारण हैं जो कि सदन को मालूम हैं और कपड़ा बेचने के लिए उन को जो इंसैंटिव दिये हैं वह भी सदन को मालूम है ।

SHRI K. RAMANI: On 26th, some 25 Members belonging to different parties of this House submitted a memorandum to the Commerce Minister asking the Government to intervene immediately to stop the threatened closure of mills by the Southern India Mill-Owners' Association. Now, the hon. Minister has said that there is no such threat and that the mills already closed have been reopened. But that is far far ago. They have now threatened to close 20 mills. May I know whether the Government will intervene and try to purchase the accumulated stock? The Mill-owners say that Rs. 11 crores worth of yarn is in stock. Here, the hon. Minister says that the situation is not so alarming. But it is alarming. Already 5000 workers are unemployed. I want to know whether they will intervene now and try to purchase, though S.T.C., some stock, stop the closure of mills and relieve the distress and give employment to all the workers?

SHRI DINESH SINGH: The hon. Member is aware that this is a continuing process by which capitalists who hold and control the mills put pressure on the workers and our effort is to give as much support to the workers as possible. What I had said was that we had received information of the likely closure of six mills out of which the State Government was giving financial assistance to four mills and that there were only two mills about which we were examining. I would like to say very frankly to the House that this is one of the most important quetsions the textile quesion that faces us. There

will be tremendous pressure from the industrialists in this and the only way we shall be able to meet it is by the House giving its utmost attention and taking decisions to support us in our efforts of modernisation and supporting the workers.

SHORT NOTICE QUESTION

Acceptance of Directorship of Bank of India by Chairman of Industrial Licensing policy inquiry Committee

SN@. 15. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Professor M. S. Thacker the Chairman of the Committee appointed to investigate into the question of issue of industrial licences to private monopoly houses in the country has accepted the directorship of the Bank of India and is attending its meetings; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) and (b). The facts regarding the question are that it is understood that Professor M. S. Thacker, Chairman of the Industiral Licensing Policy Inquiry Committee was invited informally to a meeting of the Board of Directors of the Bank of India on the 28th March, 1968, to let them know his decision on the offer made to him of Directorship on the Board of the Bank. After telling them that he required three to four weeks to consider his decision, Professor Thacker came away from the meeting. Subsequently, the Government have been informed that he has declined the offer. In the circumstances it is not proposed by Government to take any further action in the matter.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: May I know from the hon. Minister whether the Government will enquire into the fact whether the Bank of India in which there are financial interests of the private monopoly houses like, Tatas, Birlas etc., offered, immediately after Prof. Thacker's appointment as the Chairman of this Committee a fat allowance of Rs. 5000 per month if he accepts the Directorship of their Board of Directors and whether, in pursuance of this offer, after the appointment as the Chairman of this Committee, Prof. Thacker went to attend the Board of Directors meeting without the knowledge of the Government or whether he informed the Minister or the Secretary that he was going to attend the Board of Directors meeting of the Bank of India in Bombay?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): It has already been mentioned in the reply that he was requested by the Bank to tell in their meeting whether he was accepting the offer or not. He went there to say that he wanted three to four weeks time to give a reply and he came away.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the hon. Minister tell us as to how many times Prof. Thacker has paid visit to certain monopoly houses after he was appointed as the Chairman of this Committee? Its terms of reference are to enquire into the licences issued to the private monopoly houses. Would he tell us how many times he has visited certain monopoly houses and will he tell us that from the log book of the car maintained. So far as I have collected the information, he has paid visits, 23 times, to one of the private monopoly houses and that is of the Birlas. He is the Chairman of such an important Committee to enquire into the present day dreadful disease of T.B. which is a new abbreviation for Tatas and Birlas. May I know whether the Government are considering, in this background whether it is possible that the Committee will function effectively